

असावारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग I--खण्ड 1 PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित



सं० 34 ] No. 34] नई दिल्ली, वृहस्पतिबार, फरवरी 19, 1998/माघ 30, 1919 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1998/MAGHA 30, 1919

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड )

## संकल्प

मई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

सं. यू-23013/7/95-एल डब्स्यू. — ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में दिनांक 10-1-96 को प्रकाशित संकल्प सं. यू-23013/7/95-एल डब्स्यू दिनांक 10-1-96 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार हेतु बोर्ड सिटी बैंक, एन. ए., नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त किए जाने के प्रशन की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है।

- 2. समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :--
- श्री लक्ष्मण रिवन्दर सिंह भारतीय मजदूर संघ, मुनिसिपल क्वार्टर्स, परेड ग्राउन्ड, जम्म-180001
- श्री वी. एस. राव, कार्यकारी प्रबंध निदेशक, बी. बी. सी. इंडस्ट्रीज लि., 6-2-913/914, तीसरी मंजिल, प्रोग्नेसिव टावर, खैराताबाद, हैदराबाद-500004
- श्री सी. बी. प्रसाद,
   अवर सचिव (आई आर)
   विक्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग.

सदस्य

सदस्य

संयोजित सदस्य' (मताधिकार के बगैर) बैंकिंग प्रभाग, ''जीवन दीप बिल्डिंग'' दूसरा तल, कमरा नं.-20, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

4. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

सदस्य

मर्ड दिल्ली--- 110001

संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

''सिटी बैंक एन. ए., नई दिल्ली की सभी शाखाओं/कार्यालयों के ऋण वितरण, प्रलेखन समीक्षा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन (एटी एम) टेप्ड ट्रांसैक्शन चैंकिंग, मेलिंग, शेयर ईश्यू चेकों की एनकोर्डिंग, कम्प्यूटर के फंक्शनों और कम्पियों के क्रेडिट विश्लेषण के कार्यों/ऑधों में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना और इसके लिए समूचित सिफारिशें करना कि क्या सिटी बैंक, एन. ए., नई दिल्ली की सभी शाखाओं/कार्यालयों में उपर्युक्त कार्यों/जॉबों में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं।''

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट हर हाल में दो माह के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

के. कृष्णामूर्ति, सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

## (Central Advisory Contract Labour Board)

## RESOLUTION

New Delhi, the 19th February, 1998

No. U-23013/7/95-LW.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of Resolution No. U-23013/7/95-LW dated 10-01-1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, dated 10-01-1996 the Central Advisory Contract Labour Board constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour system in the establishment of CITY BANK, N.A., New Delhi.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:—

 Shri Lakshman Ravinder Singh, Bhartiya Mazdoor Sangh, Municipal Quarters, Parade Ground, Jammu-180001 Member

(2) Shri V. S. Rao, Executing Managing Director, V. B. C. Industries, Ltd., 6-2-913/914, 3rd Floor, Progressive Tower, Khairatabad, Hyderabad-500004. Member

(3) Shri C. B. Prasad,
Under Secretary(IR),
Ministry of Finance,
Deptt. of Economic Affairs,
Banking Division,
'Jeevan Deep Building',
2nd Floor, Room No. 20,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Co-opted Member (Without voting right)

(4) The Regional Labour Commissioner (Central), New Delhi-110001.

Member Convener 3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:—

"To study the working of contract labour system in works/jobs of loan disbursement, documentation review, automatic teller machine (ATM) taped transaction cheking, mailing, share issues, encoding of cheques functioning of computers and credit analysis of companies of all branches/offices of CITY BANK N.A. in New Delhi and keeping in view of the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and to make suitable recommendation whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the all branches/offices of CITY BANK N.A. in New Delhi should be prohibited".

4. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee would submit its report within two months without fail.

K. KRISHNAMURTHY, Secy.